MR. CHAIRMAN : He wants to know whether you will keep the prices stable.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : I am asking about the price rise per cubic metre of gas and naphtha during the last 10 years. What is the price rise ?

SHRI B. SHANKARANAND : I will give the exact fiugres. The price rise of naphtha was there in 1984-85. Then in 1990-91 it was Rs. 803 and this year it is Rs. 401.

MR. CHAIRMAN : You have again raised it.

SHRI B. SHANKARANAND : Yes. Regarding fuel oil, the price was raised in 1981, then in 1984-85 and again in 1990-91. I can give the figures of these products to the hon. Member.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : There has been much more rise. I want to know, what is the price rise so that the people can know ?

MR. CHAIRMAN : He can only talk about the raw material.

SHRI B. SHANKARANAND : These products are for the manufacture of fertilizers. *(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN : He is trying to keep them as low as possible.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : I want to seek your protection. This information is not correct. There is a lot of exploitation.

MR. CHAIRMAN : He is giving specific answer relating to the specific price rise. What else do you require ?

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : He has given the figures of the price rise of naphtha, not of gas.

SHRI B. SHANKARANAND : I do not have figures about gas.

MR. CHAIRMAN : He requires notice for that.

SHRIMATI MIRA DAS : Sir, how many oil fields are so far exploited and has the Government made any plans to make them more viable for useful purposes of life ? And what is the target in the Eighth Plan ?

MR. CHAIRMAN : Do you want to know the oil production target ?

SHRIMATI MIRA DAS : How many oil fields are explored ?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : How many oil fields have been prospected ?

MR. CHAIRMAN : Do you want to know about prospecting ?

SHRIMATI MIRA DAS : Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN : How many oil fields have been prospected and have been found productive ? Is that your question ?

SHRIMATI MIRA DAS : Yes, Sir. .. *(Interruptions)*. ....

SHRI B. SHANKARANAND : Sir, as I said earlier, the oil fields are to be developed, and for their development seismic and other geological survey also has to take place. Having done that, I have already said, 72 blocks have already been found to be offered to the companies for exploitation.

असम में उग्रवादी गतिविधियों में विदेशी हाथ

*42. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि असम में उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में पाकिस्तान तथा बंगलादेश का हाथ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE

IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have taken up the matter with the Government of Bangladesh and Pakistan.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान और बंगलादेश का हाथ उल्फा उग्रवादियों को बढ़ावा देने में असम में है । इस संबंध में बंगलादेश और पाकिस्तान के साथ बातचीत की जा रही है । असम के मुख्य मंत्री माननीय श्री हितेश्वर सैकिया ने विधान सभा में स्वीकार किया है कि असम में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान और बंगलादेश सरकार प्रमाणिक रूप से जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने पंजाब और कश्मीर में तो आतंक मचा हो रखा है, अब यह साबित हो चुका है कि भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बंगलादेश में शिविर बना कर के वहां उसके निर्देश में, उसकी सहायता से, उसके धन से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे राष्ट्र के लिए एकता और अखण्डता को गम्भीर खतरा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कि यह जो घृणित गतिविधियां भारत सरकार के खिलाफ उल्फा के माध्यम से पाकिस्तान और बंगलादेश को केन्द्र बना कर के कर रहा है इससे मानवीयता सिसक रही है । क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने उठाया है । यह हयुमेन राइट्स का वायोलेशन हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस जगत में इस मामले को (व्यवधान) मैं बिलकुल रेलेवेंट बोल रहा हूं (व्यवधान)

श्री सभापति : आप प्रश्न कर लीजिए ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : सभापति महोदय मेरा प्रश्न यह है कि यू० एन० ओ० के सेक्रेटरी जनरल अभी इस देश में आए थे । क्या उन से इस मसले पर कोई बात की गई है ? सरकार ने स्वीकार किया है असम के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार को सारी सूचना दी है, वह डाकुमेंट क्या है ? अब तक जो आपने आप्रेशन राइनो किया है उसमें कितने उल्फा उग्रवादी पकड़े गये हैं ? जो डाकुमेंटरी प्रूफ आपकेपास है, बंगलादेश और पाकिस्तान से इस संबंध में क्या बातचीत की है, मैं उसकी जानकारी चाहता हूं ।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN) : Sir, it is not only after the Chief Minister had informed us, but even before that also we have been taking up this issue with the respective Governments of both Pakistan and Bangladesh. It is a continuous thing which we have been doing and telling them that interference in the internal affairs of India will not be tolerated. Both the countries have been informed. There is no question of taking up this issue with the Secretary-General of the U.N.O. We would like to keep this at the bilateral level.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी अभी यू० एन० ओ० के जनरल सेक्रेट्री आये थे क्या उनसे कोई बातचीत हुई थी . . .

श्री एस० बी० चव्हाण : वही जवाब दिया था . . . (व्यवधान)

श्री सभापति : जवाब दे दिया कि द्विपक्षीय रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नहीं ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : महोदय, 23 मार्च को उल्फा के चेयरमैन, अरविन्द राज खोवा, वाईस चेयरमन प्रदीप गोगोई तथा जनरल सेक्रेट्री अनूप चेटिया सीमा पार करके बंगलादेश गये और वहां पाकिस्तानी एजेंटों के कहने पर इन तीनों उल्फा उग्रवादियों ने भारत सरकार की असम समस्या को हल करने के लिए किसी विश्रान्त वर्तालाप में न शामिल होने की सार्वजनिक घोषणा की। यदि ऐसा है तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन तीनों उल्फा उग्रवादियों को सीमा पार करने से रोका क्यों नहीं गया। इस समय ये लोग कहां हैं ?

भारत बंगलादेश सीमा सील करने हेतु भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? असम समस्या को हल करने के लिए उल्फा के साथ-साथ सभी असंतुष्ट गुटों तथा संगठनों को शांति वार्तालाप में शामिल करने के बारे में सरकार ने क्या प्रयास किये हैं और अभी तक क्या उनके परिणाम सामने आए हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : सभापति महोदया, आनरेबुल मेम्बर ने जो सवाल पूछा है उसके बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि उल्फा की तरफ से जो सरेंडर की बात चल रही थी, नेगोशिएशन करके एक अंडरस्टैंडिंग–इंडियन कांस्टीट्यूशन को मानने के लिए–एक नतीजे पर आना चाहते थे लेकिन उस नतीजे पर आने से पहले उनके जो दो-तीन खास लोग जो बंगलादेश में उस वक्त थे उनसे बातचीत करने के लिए वे गये थे और वहां पर, इस बात की जानकारी गवर्नमेंट को है कि उनकी तरफ से इस बात को कहा गया कि कोई सेटिलमेंट न किया जाए । पाकिस्तान की जो आई० एस० आई० की एजेंसी वहां पर है उनकी तरफ से उनके ऊपर काफी दबाव डालकर किसी अंडरस्टैंडिंग पर आप न आयें इस किस्म की बात कही गयी । इसकी जानकारी गवर्नमेंट के पास है ।

SHRI P. UPENDRA : Sir, the army has been deployed in great strength in Assam to contain the ULFA activities. I would like to know from the hon. Minister to what extent the army has succeeded in containing the extremist menace and also whether it has been given the responsibility of stopping the infiltration from across the border. What happened to the proposal to have barbed-wire fencing across the border ?

Also, has the Home Minister received any complaints of excesses by the army ? I do not believe in them. But some sources have alleged them, and it is necessary to enquire into each complaint so that the army's reputation is not spoiled and also that the people are not alienated. Has he received such complaints ?

SHRI S. B. CHAVAN : So far as the first part of the question is concerned, in fact, the army has been deployed in a big way there. But, unfortunately, the army operations had to be suspended on the request of the hon. Chief Minister in Assam. Operation Bajrang was also started. It was suspended for some time. Thereafter, again the whole activity was started. Operation Rhino had to be started on 15-9-91. Thereafter, negotiations were started. They were suspended. Again on 1-4-92 we had to start the same Operation. A large number of these ULFA activists have been either captured or they have surrendered themselves. They are surrendering in a big way. But a final settlement is still not in sight.

There is with me a report which shows that some excesses have been committed. The army officers are looking into the matter.

SHRI P. UPENDRA : What about the barbed-wire fencing ?

SHRI S. B. CHAVAN : About the barbed-wire fencing and other things, in fact, tremendous amount, almost Rs. 372 crores, has been sanctioned by the Government of India. Almost 590 or 596 kms. of barbed-wire fencing has to be undertaken. Unfortunately, in that area the main problem seems to be about the land which has to be provided by the State Government. The construction also certainly of the barbed-wire fencing and also of the border roads in Assam has to be done by the local P.W.D. Unfortunately, the progress has not been satisfactory. Tomorrow we have called a meeting of the Chief Secretaries of all the concerned States to discuss why they have slowed it down. In fact, there is no paucity of funds. Funds can be provided. They have to provide the land and go ahead with the barbed-wire fencing as well as the construction of roads.

श्री राम नरेश यादव : महोदय, असम की जो स्थिति है, उससे जिस तरह की मांगे उल्फा के लोग, आतंकवादी उठा रहे हैं, उससे

हमारी सावरेनटी को जो मांग कर रहे है, उससे राष्ट्रीय एकता को बराबर खतरा पैदा हो गया है, यह बात अपनी जगह पर सही है ।

यह भी एक बात आती है कि जो वहां से आते है, उनके पास सोफिस्टिकेटिड आर्म्स हैं, तरह-तरह के प्रशिक्षण प्राप्त करके आते है और आकर के अपनी आतंकवादी गतिविधियों से जिस तरह से वहां पर अस्थिरता का वातावरण पैदा कर दिया है, वह देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है ।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो फेंसिंग की बात हो रही है कि वहां से वे न आने पावें, इसके अतिरिक्त और कौन से कदम सरहद पर उठाये गये हैं, ताकि जो नित्य प्रति आना-जाना लगा रहता है, वहां के लोग आते है और हथियार लेकर आते है और अभी जैसा कि उनका चेयरमैन, वाईस-चेयरमैन, उनका सेक्रेटरी-जनरल यहां से भाग कर बंगलादेश में जाकर शरण पा रहे हैं और बंगलादेश उनको संरक्षण दे रहा है ।

इसलिए इस आवागमन को रोकने के लिए और हथियार वहां से न आने पाये, इसको रोकने के लिए सरकार बार्डर पर कौन से कदम उठा रही है, ताकि यह आने-जाने का क्रम न रहे और हथियार न आ सकें और आकर वे वहां पर असहिष्णुता का वातावरण न पैदा कर सकें क्योंकि पिछली जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, उसके समय में उलफा की जो गतिविधियां बढ़ीं वह खतरनाक रहीं ।

इसलिए इस बात को सोचते हुए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाया है, वही मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं ।

श्री एस० बी० चव्हाण : उलफा के जो एक्टिविस्ट्स हैं, उनमें से आलमोस्ट 75 प्रतिशत लोग अब तक सरंडर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो उनका मिलिटेंट सैक्शन है, वह जब तक सरंडर नहीं करता है, और पूरे हथियारों के साथ सरंडर नहीं होता है, उस वक्त तक कम्पलीट पीस उस एरिया के अंदर होना मुश्किल दिखता है । इसलिए एक तरफ नेगोसिएशंस तो चलती रहेंगी, लेकिन बार्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन की तरफ से वह सारी रोड्स बनाई जायें, वहां पर फेंसिंग हो, बार्डर पर आब्जरवेशन पोस्ट कायम किये जाये और बीच में जो वहां से पैरा-मिलिटरी फोर्स को विदड्रा किया था उसको फिर से वहां पर रेस्टोर करने की बात, यह चारों की चारों चीजें हम करते जा रहे हैं ।

SHRI RAJ MOHAN GANDHI : Will the Minister be good enough to state whether in view of the crucial relevance of Bangladesh to a solution of the problems in the North-East, the Government is taking steps for a meeting at the level of Heads of Government between India and Bangladesh ? If so, what are the steps taken in this regard ? If not, why not ?

SHRI S. B. CHAVAN : In this respect there was some kind of a discussion between the hon. Prime Minister of Bangladesh and our Prime Minister. Thereafter, in fact, in principle they agreed that they would like to keep peace and would not like to interfere in India's internal matters. But still on ground it does not get reflected. That is why they require some kind of evidence. That evidence has been made available and they are now fully convinced about it. Let us see how they react to it.

SHRI V. NARAYANASAMY : The same question was put by me on the first day, on 27th.

MR. CHAIRMAN : Why are you repeating it ?

SHRI V. NARAYANASAMY : It was put before the External Affairs Minister. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : This Government is consistent.

SHRI V. NARAYANASAMY : In my question I had said that Bangladesh an

Pakistan are helping the ULFA activists. Therefore, my question had gone to the External Affairs Ministry. The reply given by the External Affairs Minister is different when it is compared to the reply given by the hon. Minister of Home here. The External Affairs Minister had said in his reply that they had contacted the Bangladesh Government and they denied any knowledge of having a support base for ULFAs in Bangladesh. But, Sir, here the reply given by the hon. Home Minister is totally different. The Minister says now we are getting in touch with the Bangladesh Government. Therefore, it is very clear that there is no coordination between the Home Ministry and the External Affairs Ministry.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : It is a very severe condemnation.

SHRI V. NARAYANASAMY : This is a very serious matter.

MR. CHAIRMAN : Come to the question, please.

SHRI V. NARAYANASAMY : I am coming to the question. Relating to the ULFA activists, their activities in Assam and the support base in Bangladesh and the intelligence support from Pakistan, the Chief Minister says the Commander-in-Chief in Assam, who is supervising the Army operations, has not taken the Chief Minister into confidence. This is the version of the Chief Minister. Therefore, I would like to know from the hon. Home Minister whether it is a fact that the Chief Minister was not taken into confidence. If so, whether the Chief Minister will be fully involved in the negotiations with the ULFA activists in the State.

SHRI S. B. CHAVAN : Sir, about the first part of the question, there is no contradiction between what the External Affairs Minister has stated on the floor of the House and what I am replying. But the only question is in the beginning they were rather reluctant to accept that there was presence of ULFA activists and I said just now that sufficient evidence has been made available to them for being fully convinced. Actually this is the point which they will have to attend to and I am sure that at the highest level we are again going to follow this up at the diplomatic level. I am sure that it gets reflected on the floor also.

SHRI V. NARAYANASAMY : The Chief Minister complained that you have not taken him into confidence during the Army operation.

SHRI S. B. CHAVAN : I am sorry, I could not get you.

SHRI V. NARAYANASAMY : The Chief Minister said that he was not taken into confidence during the Army operation in Assam against the ULFA.

SHRI S. B. CHAVAN : I do not think it is correct. There is a Coordination Committee where the Chief Minister himself is also present. So there is no question of starting the Army operation without the knowledge of the Chief Minister.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सभापति जी, यह समय-समय पर गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि न केवल आसाम में "उलफा" के लिए बल्कि पंजाब में भी काश्मीर में भी पाकिस्तान और इधर बंगला देश इनकी सहायता आतंकवादियों को मिल रही है। इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने बीच में कुछ मीटिंग्ज भी बुलाई हैं कोआर्डिनेशन या संयुक्त कार्यवाही के लिए जिन-जिन प्रदेशों में आतंकवाद चल रहा है उसके बारे में, मैं गृह मंत्री जी से दो बातें पूछना चाहता हूं। पहली बात यह कि जैसे आपने कहा कि आपने पाकिस्तान और बंगला देश को यह चेतावनी दी है कि वह हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें इसके बावजूद भी वह हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह हस्तक्षेप आपकी चेतावनी के बावजूद जारी है ? अगर जारी है तो इसके बारे में आपकी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से उस एक्शन का जवाब, उस कार्यवाही का जवाब क्या दिया जा रहा है ? दूसरा यह कि इन तीनों प्रदेशों में इंटरस्टेट लेवल पर भी अगर

आतंकवादियों का आपस में कोई लिंक है तो उसके बारे में सरकार उसका क्या उपाय कर रही है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : पहले सवाल का जवाब यह है कि यह डिप्लोमेटिक लैवल पर ही बातें हो सकती हैं, इससे ज्यादा गवर्नमेंट इसमें और दूसरी बात कर नहीं पाएगी । दूसरा जो हथियार लेकर आतंवादी यहां पर बार्डर क्रास करके इंडिया में आते हैं उनको रोकने के लिए मैंने पहले ही कहा 3-4 कदम हम उठा रहे हैं । लेकिन उसकी गति कम है, यह मैं खुद मानने के लिए तैयार हूं । कल उन चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग बुला कर उनकी तरह से लैंड एक्विजीशन इमीडिएटली हो वह जमीन कब्जे में देने के बाद फिर उसके यह आगे की कार्यवाही करना आसान हो जाएगा ।

Non-approval of production targets recommended by ONGC

*43. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production targets set for the year 1991-92 and 1992-93 as recommended by the Oil and Natural Gas Commission have not been approved by Government ;

(b) if so, what are the reasons therefor ; and

(c) whether the failure to do so would have an adverse effect on the working of the Oil and Natural Gas Commission ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) and (b) Different production targets were recommended by ONGC from time to time. However, the final revised target was fixed at 29 million tonnes for 1991-92. The target for the year 1992-93 is in the process of being finalised.

(c) According to ONGC, no, Sir.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : Sir, the hon. Minister has said that different production targets were recommended by the ONGC from time to time. I want to know the date on which the targets were recommended to the Government by the ONGC for 1991-92. And what is the date on which the same was ultimately approved and if there is a time-lag between them—whatever may be the time-lag—what is the reason therefor ? This is my first supplementary, Sir. For 1992-93, as said in the reply, the matter is under process. When was the target recommended by the ONGC for 1992-93 to the Government ? What is the time that has passed ? And why they have not been approved so far ? This is the first supplementary.

SHRI B. SHANKARANAND : Sir, to make things clear, targets are estimated depending on various factors by the ONGC initially. Now, the process of fixing targets for the year 1991-92 started before we came to power, that is, before June, 1991.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : I have not asked when you came to power. I have asked for the date. I want no exculpating Statements from you.

SHRI B. SHANKARANAND : I may not be able to give the .... (*Interruption*).

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : I want to know when you got the target.

SHRI B. SHANKARANAND : I am just giving the date.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : I request the hon. Minister not to sidetrack. The time available is limited. At least there are ten minutes if he is not trying to side-track.

SHRI B. SHANKARANAND : For the benefit of the hon. Member and of the House, I can give the entire dates, the targets given and the remarks, if the House is willing to listen. I have the full details with me.